Expansion of Postal Service in Hilly and Rural Areas

2207. SHRI SATISH CHANDRA SITARAM PRADHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have undertaken any survey to modernise the postal services through the induction of new technology in the country; and

(b) if so, the steps taken/proposed to be taken by Government for expansion of postal services in inaccessible, hilly parts and rural areas of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI KABINDRA PURKAYASTHA): (a) and (b) Yes, Sir. The Department of Posts during the last few years has been inducting computer and communication technologies into the Post. Computer based multipurpose counter machines have been installed where the customer can carry out all transactions at a single window. These machines have been installed in remote areas like Rekong PO, Badi (HP), Kathua (J&K), Imphal, Kohima, Aizwal, Itanagar etc. 75 VSATs (Very Small Aperture Terminals) have been installed alongwith 610 Extended Satellite Money Order Stations for money transfer from major urban centres to the hinterland including inaccessible, hilly parts and other rural areas such as Rynjah (Shillong), Nogpah (Shimla), Joginder Nagar (HP), Kawarati (Lakshdweep) etc.

दूरभाषों की "मल्टी एक्सेस रूरल रेडियो" प्रणाली

2208. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एम.ए.आर.आर. प्रणालीयुक्त दूरभाष केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है,

(ख) इस प्रणाली के ठीक से कार्य न कर पाने के क्या कारण है,

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में किस वैकल्पिक प्रणाली को अपनाया जाएगा, और

(घ) इस प्रणाली वाले केन्द्रों को बदलने के लिए वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ) : (क) देश में एमएआरआर प्रणालियों से सज्जित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं। (नीचे देखिए)

(ख) निम्नलिखित कारणों से एमएआरआर प्रणालियों का निष्पादन आशा से कम रहा है :-

(i) एमएआरआर प्रौद्योगिकी का कम विश्वसनीय होना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में बार-बार बिजली जाना तथा काफी देर बिजली न जाना।

(iii) उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ब्रिकी के बाद अपेक्षित सेवाएं न देना।

(iv) ऐसे स्थानों पर पहुंचने में कठिनाई होना/ उनका दुर्गम् होना, जहां उपस्कर लगाए गएं हैं।

(v) बीपीटी धारकों द्वारा पर्याप्त ध्यान न दिया जाना तथा ग्रामवासियों द्वारा बैटरियों का दुरूपयोग किया जाना।

(ग) एक्सचेंज से 3-5 कि.मी. की कम दूरी के लिए लैण्ड लाइनों के इस्तेमाल के अतिरिक्त सरकार, 1999-2000 से शामिल किए जाने वाली निम्नलिखित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों पर विचार कर रहीं हैं :

(i) स्थानीय लूप में बेतार/डब्ल्यू एस एल)

(ii) सी-डॉट टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस/प्वाइंट-टू-मल्टी प्वाइंट प्रणालियों।

(iii) दूरस्थ तथा दुर्गम गांवों में उपग्रह प्रौद्योगिकी।

(घ) जहां पहले एमएआरआर आधारित वीपीटी पर सौर-पैनल नहीं लगाएं गए हैं उन पर सौर पैनल लगाना

- एसएसए तथा सर्किल स्तर पर दैनिक रूप से वीपीटी दोषों पर निगरानी रखना।

-विनिर्माताओं के साथ वार्षिक अनुरक्षण ठेके किए जा रहें हैं।

-दोषयुक्त वीपीटी को ठीक करने के लिए दूरसंचार विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

- दूरसंचार सर्किलों के महत्वपूर्ण स्थानों पर मरम्मत केन्द्र खोले जा रहें हैं।